भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 32

20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण

*32. **श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा:**

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में इस दिशा में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या आधुनिक सहकारी क्षेत्र जमीनी स्तर पर कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान में सहायक होगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (SHRI AMIT SHAH)

(क) से (ग): सदन के पटल पर एक विवरणी रखी गई है ।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 32 के भाग (क) से (ग) का उत्तर जिसे दिनांक 20 जुलाई, 2022 को दिया जाना है की संदर्भित विवरणी

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु विभिन्न पहल की हैं, जिसमें 2,516 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की अखिल भारतीय परियोजना, पैक्स को बहुउद्देशीय जीवंत आर्थिक इकाईयों में परिवर्तन के लिए प्रारूप मॉडल उप-नियमों का निर्माण, सहकारिताओं के सर्वांगीण विकास को लक्षित करते हुए सहकार से समृद्धि योजना बनाना, सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण को आधुनिक और पेशेवर बनाने की योजना आदि । देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय एक नई सहकारिता नीति भी ला रहा है और सभी हितधारकों की परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी कार्य कर रहा है ।

इस मंत्रालय की सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों के सहकारी क्षेत्र को पुनरुद्धार करने करने को लक्षित है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने उत्तर प्रदेश में सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए 252.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है । इसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**कार्यकलाप**	**निर्गत राशि (करोड़ रुपए में)**
1	15 जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)	50.077
2	न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालन हेतु प्रादेशिक सहकारी संघ लिमिटेड, (पीसीयू) लखनऊ को सहायता	200
3	एफपीओ का गठन एवं संवर्धन	0.84
4	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कार्यशालाएं	0.032
5	डीसीसीबी का कंप्यूटरीकरण	1.383
	कुल	**252.332**

उपर्युक्त के अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) द्वारा 82 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए जिससे 3,071 प्रतिभागियों के क्षमता विकास को सहायता मिली ।

मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों, विशेषरूप से पैक्स के कंप्यूटरीकरण तथा पैक्स के मॉडल उप-नियमों के साथ-साथ सहकार से समृद्धि की नई योजना के लाभ से पैक्स के कार्यकलापों में विविधता लाकर उन्हें ग्रामीण/पंचायत स्तर पर जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित करेगी । सहकारिता एकमात्र ऐसा व्यावसायिक मॉडल है जहां समावेशी विकास एक अभिन्न अंग है । इससे न सिर्फ आधारभूत स्तर पर अंतिम व्यक्ति की आय वृद्धि होगी बल्कि उन्हें लाभ में बराबर हिस्सेदारी भी प्राप्त हो सकेगी ।

*****